the Richter Scale is common in pen-'insular India. These are considered of minor nature because of insignificant damage caused by them. The present seismic activity is already in decaying trend and therefore there appears to be no cause for alarm.

Allegations of corruption against a scientist

1217. SHRI MOSTAFA BIN QUASEM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that allegations of corruption are pending against a Scientist (C grade) at CSIR;

(b) if so, whether vigilance department has been entrusted with the . enquiry; and

(c) what are the findings of the enquiry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE (SHRI K. R. NARAYANAN): (a) No allegations of corruption are pending equiry against any Scientist ('C' grade) at CSIR.

(b) and (c) Do not arise.

राजस्थान में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्ति

12 8. **श्री संतोष बागड़ोदिया :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में राजस्थान में कितने प्रतिशत व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे थे ;

(ख) उत्तरवर्ती प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के अन्त में इस राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना था ;

(ग) गरीबी दूर करने के लिए इस राज्य को कितने प्रतिशत योजना-आवंटन किया गया ; और

(घ) शेष लोगों को कब तक गरीबी की रेखा से ऊपर ला दिये जाने की सम्भावना है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) तथा (ख) गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के अनुमान पारिवारिक उपभोक्ता व्यय से संबद्ध राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़े के आधार पर तैयार किए जाते हैं। अतः गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के ये अनुमान केवल वर्ष 1972-73 1977-78 तथा 1983–84 के लिए उपलब्ध हैं। प्रत्येक उत्तरवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति पर गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 1972–73, 1977–78 तथा 1983–84 के लिए गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के अनुमानों को राज्यवार दर्शाने वाले विवरण संलग्न हैं, जिनमें राजस्थान राज्य के संबंध में भी सूचना निहित है। [देखिए परिशिष्ट CXLVII, अनुपत्र संख्या 47]

(ग) ऐसी योजनाओं जिनसे गरीबी उन्मूलन पर प्रभाव पड़ता हो, के अन्तर्गत अधिकांश विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। गरीबी की समस्याओं पर सीधा प्रहार करने वाले तीन प्रमुख कार्यक्रम ये हैं :—एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम।

राजस्थान राज्य के लिए इन कार्यक्रमों के संबंध में योजना आवंटनों की प्रतिशतता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। [देखिए परिशिष्ट CXLVII, अनुपत्र संख्या 48].

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिए गए अनुमानों के अनुसार देश में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की प्रतिशतता में सन् 2000 तक 5 प्रतिशत तक

कमी आने की आशा है। तथापि, इस संबंध में राज्यवार अनुमान उपलब्ध नहीं है।

रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिए सहायता

1219. **श्री संतोष बागड़ोदिया :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने अपने रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता देने का अनुरोध किया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को कितनी धनराशि देने का विचार रखती है; और

(ग) यदि धन नहीं दिया जाना है, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) छठी योजना के दौरान, रेगिस्तानी/क्षेत्र विकास कार्यक्रम एक केन्द्र आयोजित योजना थी जिसके अनुसार, केन्द्र और राज्यों के मध्य शेयर 50:50 था। सातवीं योजना के प्रारंभ में, राजस्थान सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के पैटर्न पर यानि राज्य में रेगिस्तानी क्षेत्र विकास के लिए 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में केन्द्रीय सहायता देने का सुझाव दिया था। इसकी तुलना में, रेगिस्तानी क्षेत्र विकास के लिए छठी योजना की केन्द्र प्रायोजित स्कीम को सातवीं योजना के दौरान 100 प्रतिशत केन्द्रीय स्कीम में परिवर्तित कर दिया गया है।

(ख) 7वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम हेतु 245 करोड़ रुपये के कुल आवंटन में से राजस्थान का हिस्सा 190 करोड़ रुपये बैठता है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Number of IAS officers to the rank of Secretaries in the Government of India

1220. SHRI YASHWANT SINHA; Will the PRIME MINISTER be pleae-ed to state:

(a) the total number of Secretaries in the Government of India belonging to the IAS, Central services and other, Statewise; and

(b) the number of posts of Secretaries are vacant and since when, Ministry/Departmentwise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM); (a) The IAS Officers-40 The Central Services Officers-25

Others — 17

Statewise number of IAS officers working as Secretaries in the Government of India is given in the Statement. (See below).

(b) One post of Speical Secretary, Home Department, has . been vacant since 1.8.1988. No other post is vacant. Government has, however, appointed the same officer as Secretary of more than one department where it is satisfied that, for the time being, the required work can be so carried out effectively.

Statement

Number of IAS Officers Statewise serving as Secretaries in the Government of India	
Andhra Pradesh	2
Bihar	2
Gujarat	
Himachal Pradesh	1
Haryana	1
Kerala	3
Karnataka	1
Maharashtra	S
Madhya Pradesh	2
Orissa	3
Punjab	2
Rajasthan	5
Tamil Nadu	4
Uttar Pradesh	7
West Bengal	8
Total	40